(ख) इन किसानों को बसाने के लिए सरकार के पास कितने एकड़ भमि है ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) द्वितीय खेतीहर मजदूर जांच के अनुसार देश में खेतीहर मजदूर परिवारों की संख्या 163 लाख थी जिनमें से लगभग 57 प्रतिशत भूमिहीन थे ।

(ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त परती भूमि सर्वेक्षण तथा सुधार समिति ने 250 एकड़ तथा इससे बड़े खण्डों में लगभग 10.8 लाख एकड़ भूमि का पता लगाया है । अनुमान है कि इस क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई भाग सरकार की सम्पत्ति है । पुनर्वास हेतु भूमि का पता लगाने के लिए कई राज्यों में 250 एकड़ से छोटे भू-खण्डों में परती भूमि के सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण का कार्य शुरू किया गया है । इसके अतिरिक्त भूदान, ग्रामदान तथा निर्धारित सीमा से ऊपर की कुछ फालतू भूमि भी उपलब्ध होगी । उस क्षेत्र के विषय में, जो कि खेतीहर मजदूरों के पुनर्वास के काम में लाया जा सकता है, ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत खेतीहर मजदूरों के पुनर्वास हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । इसी कार्य के लिये राज्य परियोजनाओं में 3.63 करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था की गई थी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों—जिनमें अधिकतर खेतीहर मजदूर ही आते हैं—की कल्याण सम्बन्धी योजनाओं में भी भूमि पर पुनर्वास की व्यवस्था मौजूद है ।

पता चला है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में जिला अधिकारियों ने खेतीहर मजदूरों में लगभग 13 लाख एकड़ भूमि बांटी है । खेतीहर मजदूरों के लिये मकानों के लिये स्थान हेतु 5 करोड़ रुपयेकी व्यवस्था की गई है ।

ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम द्वारा, जिस पर कि तीसरी योजना की अवधि में लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है, अतिरिक्त कार्य अवसर प्रदान करने से भी खेतीहर मजदूरों के पुनर्वास में काफी सहायता मिलेगी ।

गाय-भैंसों के साथ निर्दयता

104. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में प्रति वर्ष लगभग दो करोड़ रुपये की गायें और भैंसे दूसरे राज्यों, विशेषकर पंजाब से, मंगाई जाती हैं, और वे बूचड़खाने में भेजने से पहले बहुत ही बुरी हालत में रखी जाती हैं और उन्हें दुहा जाता है ;

(ख) क्या सरकार के पास इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई हैं कि गाय, भैंसों के ये व्यापारी लोग दूध दुहने का बड़ा ही बेरहमी का तरीका अपनाते हैं और उनके बछड़ों को भूखा मार डालते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी गाय भैंसों को बचाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Hindu Religious Endowment Commission

105. **Shri Hem Raj**: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether all the State Governments have now responded to the